

RAJYA SABHA

Tuesday, the 16th May, 1995/26th
Vaisakha, 1917 (Saka)

The House met at eleven of the
clock, Mr. Chairman in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*561. [The questioner (Shri L Ramji Lal)
was absent. For answer, vide Col. intra]

मध्य प्रदेश में सांची में विदेशी पर्यटकों

*562. श्री राघवजी : क्या नागर
विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत
तीन वर्षों के दौरान सांची (मध्य प्रदेश)
में विदेशी पर्यटकों की संख्या प्रतिवर्ष
बढ़ी है ;

(ख) यदि हां, तो सांची में पर्यटकों
की सुख-सुविधा के लिये मंत्रालय द्वारा
गत तीन वर्षों के दौरान व्यय की गई
धनराशि का व्योरा क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का
उत्तर "ना" हो, तो इसके क्या कारण हैं
और क्या निकट भविष्य में इस दिशा
में कोई योजना तैयार की जायेगी ?

नागर विमानन और पर्यटन मंत्री
(श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग)
एक विवरण पत्र सभा पटल पर रखा
गया है ।

बिबरण

(क) जी, हां । पिछले तीन वर्षों
के दौरान सांची में विदेशी पर्यटक आम-
न में अनुकूल वृद्धि रही है । 1992,
1993 और 1994 के दौरान सांची का

दौरा करने वाले विदेशी पर्यटकों
संख्या निम्नानुसार थी :—

वर्ष	पर्यटक प्राप्त	% परिवर्तन
1992	1573	—
1993	1899	(+) 20.7
1994	2453	(+) 29.2

(ख) और (ग) किसी स्थान पर
पर्यटक आधारभूत सुविधाओं का विकास
करना मूलतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी
होती है । पर्यटन विभाग, भारत सरकार,
पर्यटक सुविधाओं के विकास हेतु राज्य
सरकारों को उनसे प्राप्त सभी प्रकार से
पूर्ण तथा दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्तावों
के आधार पर वित्तीय सहायता प्रदान करती
है । पिछले तीन वर्षों के दौरान, सांची
में पर्यटक सुविधाएं प्रदान करने के लिए,
मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव
प्राप्त नहीं हुआ है । 1985-86 में,
पर्यटन विभाग ने, सांची में एक कैफेटेरिया
और प्रसाधन/पेय जल सुविधाओं के निर्माण
हेतु 11.32 लाख रु. की राशि की
आर्थिक सहायता रिलीज की थी । यदि
राज्य सरकार द्वारा सभी प्रकार से पूर्ण
एवं दिशानिर्देशों के अनुरूप प्रस्ताव भेजा
जाए, तो सांची में केन्द्रीय वित्तीय सहायता
के माध्यम से अतिरिक्त पर्यटक सुविधाएं
प्रदान कराई जा सकती हैं ।

श्री राघवजी : सभापति जी, सांची
में विश्व प्रसिद्ध स्तूप है और उसके द्वार
जो बने हैं, वे अद्वितीय हैं पुरातत्व की
दृष्टि से भी और बौद्ध धर्म के तीर्थ की
दृष्टि से भी । सांची का इतना बड़ा
महत्व होने के बावजूद भी और जहां पर
प्रतिवर्ष पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है,
जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर
में बताया है कि 1994 में 29.2 प्रतिशत
विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ गई लेकिन
इसके बावजूद भी 1985-86 में केवल
11 लाख रुपये कैफेटेरिया के खर्च हुए ।
इसके अलावा आज तक दस सालों में एक

रूपया भी केन्द्रीय पर्यटन विकास विभाग न वहाँ पर खर्च नहीं किया जबकि वहाँ पर आवास के लिए भी काफी अनुविधा है, केवल एक टूरिस्ट लाज है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार विदेशी पर्यटकों के लिए भी और देशी पर्यटकों के लिए भी वहाँ पर आवास सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए किसी योजना पर विचार करेगी और क्या होलिडे-होम या ऐसी किसी प्रकार की योजना के बारे में विचार करेगी ?

श्रीमती मुखर्जी : सर, यह सही है कि सांची में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है और प्राचीन काल से लेकर आज तक भारत में तीर्थ यात्रा पर्यटन का एक बड़ा हिस्सा बनी रही है। हमारी यह कोशिश है कि हम तीर्थ यात्रियों को सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ लेकिन एक बात मैं अपने आनरेबल मैम्बर को बताना चाहती हूँ कि जो डेवलपमेंट आफ इनफ्रास्ट्रक्चर है, वह प्राइमरिली स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम डिपार्टमेंट आफ टूरिज्म से कुछ आर्थिक सहायता उनको देते हैं। वे अपने प्रोजेक्ट्स बना कर लाते हैं और हम उनको सहायता देते हैं। जो भी वे प्रोजेक्ट लाते हैं, हमारी यह कोशिश होती है कि हम उनको सहायता दें। जहाँ तक सांची का सवाल है, यह सही है कि हमने सिर्फ 11 लाख रूपया दिया है लेकिन जैसा मैंने बताया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट हमसे और पैसा मांगेगी तो हम जरूर देंगे। वहाँ पर भी सांची में एक ट्रेवल्स लाज है, एक कैफेटेरिया है, उसके साथ दो कमरे हैं, एक पी. डब्ल्यू. डी. गैस्ट हाउस है और वहाँ पर एक महाबोधी सोसायटी का डामिटरी टाइप रेस्ट हाउस है। इसके अलावा भोपाल जो उसके नजदीक पड़ता है, वहाँ पर भी काफी ऐकॉमोडेशन अवैलेबल है और मेरे पास उसके आंकड़े हैं। तकरीबन 306 कमरे भोपाल में भी हैं। इसलिए हमारी तरफ से अगर कुछ और कमरे या अन्य सुविधाएँ उनको चाहिए होंगी तो हम उनको जरूर सहायता देंगे।

श्री राधवजी : सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय का इस बात

लिए आभार मानता हूँ कि उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि अगर राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो वे इस पर विचार करेंगे लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि जिन प्रकार से खजुराहो में हवाई अड्डा है और वहाँ पर हवाई यात्रा से सीधे खजुराहो पहुँचा जा सकता है, खजुराहो से किसी भी दृष्टि से सांची कम नहीं है और वहाँ पर पहुँचने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। खजुराहो और सांची को भी जोड़ा जा सकता था और यह कोई राज्य सरकार का मामला तो नहीं है, सीधे-सीधे केन्द्र सरकार के उद्भयन विभाग का सामला है। तो हवाई अड्डा नहीं है वहाँ पर नंबर एक और नंबर दो, अगर वहाँ पर यात्री पहुँच जाए तो उसके आस-पास जितने स्थल हैं देखने के लिए, उदयगिरी केवल विदिशा की, हेलिओडोर पिलर विदिशा का और सप्तधारा, ये तीन-चार स्थान ऐसे हैं जहाँ पहुँचने के लिए कोई भी व्यवस्था, किसी वाहन की व्यवस्था नहीं है वहाँ पर। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि क्या वहाँ पर हवाई यात्रा की व्यवस्था करेंगे ताकि टूरिस्ट सीधे सांची में जाकर ठहर सकें और उनको भोपाल जाने की आवश्यकता न पड़े, क्या इस तरह का कोई प्रबंध आप करेंगे ? दूसरा, मताब्दी सांची रेलवे स्टेशन से ही गुजरती है तो मताब्दी को वहाँ रोकने के लिए भी सरकार प्रयास करेगी ? साथ ही आसपास के स्थलों को देखने के लिए टूरिस्ट बसों की व्यवस्था, क्या आपका मंत्रालय करने की स्थिति में है, इसका आश्वासन क्या आप दे सकते हैं ?

श्रीमती मुखर्जी : पहली बात तो यह है कि जहाँ तक एयर कनेक्शन का सवाल है, भोपाल के लिए डाइरेक्ट फ्लाइट है, इंडियन एयर लाईंस की और अर्चना एयरवेज की फ्लाइट्स जाती हैं। रेल की भी वहाँ लाइन है जो झांसी और इटारसी सेक्शन की है। सांची के बारे में बात करनी पड़ेगी, देखना होगा कि उसका क्या हो सकता है। इस बारे में मैं इस टाइम कुछ नहीं कह सकती कि वहाँ मताब्दी टाइप ट्रेन चलेगी या नहीं

चलेगी। जहाँ तक वहाँ के नजदीक के स्थानों को देखने का सवाल है वह प्राइवेट इंटरप्रोनेस से भी हम कोशिश करते हैं कि वे अपनी लक्जरी बसेस टुरिस्ट्स के लिए चलायें और स्टेट गवर्नमेंट भी चलाये।

श्री शंकर बयाल सिंह : सभापति जी सांची एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल भी है और इसका प्राचीन इतिहास हमारी संस्कृति और इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास कोई ऐसी योजना है, जिसमें जितने भी बौद्ध स्थल हैं, उनके लिए एक समान कार्य योजना बनाकर पर्यटन की अधिक से अधिक सुविधा दी जाए, जिससे विदेशी पर्यटकों के लिए अधिक से अधिक सुविधा, जाने की, ठहरने की और देखने की हो सके। मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि क्या जापान सरकार ने या जापान के महाबोधि सोसाइटी ने या फूजी गुरुजी, जो जापान के सबसे बड़े बौद्ध संत थे उनकी सोसाइटी ने भारत सरकार को इस तरह का कोई आश्वासन दिया है कि वे आर्थिक सहयोग और सहायता देने के लिए तैयार हैं ताकि भारत और नेपाल में जो भी बौद्ध स्थल हैं, उन्हें एक सर्किट के साथ जोड़ा जा सके? यदि हाँ, तो इस संबंध में सरकार क्या कर रही है?

श्रीमती सुखबंस कौर : हमारे जितने भी बौद्ध धर्म स्थान हैं, अलग अलग स्टेट्स में इसके लिए हम लोगों ने कई स्कीमें बनाई हैं। हमारी कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ सुविधाएँ उपलब्ध करायें। हम लोगों ने बिहार में, यू०पी० में और सांची में थोड़ा किया है। इसके अलावा हम लोगों ने आन्ध्र प्रदेश में भी पैसा दिया है और वहाँ करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्कीम सारे ही बौद्ध धर्म के स्थानों के लिए एक जैसी हों, अभी कोई ऐसा विचार नहीं है। अलग अलग जगहों के लिए अलग-अलग किया गया है।

जहाँ तक जापान का सवाल है वहाँ प्रो० ई० बी० एस० फंड जो बिहार और

यू०पी० के लिए दिया गया था, अभी वह खर्च हो रहा है। ऐसे आफर हमारे पास आते रहे हैं और बातचीत होती रहती है। लेकिन अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है कि जापान से हम पैसा लेंगे या नहीं लेंगे।

श्री शंकर बयाल सिंह : यह तो भारत सरकार की अक्षमता है कि लोग देने के लिए तैयार हैं लेकिन वह लेने के लिए तैयार नहीं है और स्वयं भी कोई योजना नहीं बना रही है। जहाँ पर जो बौद्ध पर्यटक आते हैं उनकी शिकायत है कि भारत सरकार इसमें सहयोग नहीं दे रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूँ कि...

श्रीमती सुखबंस कौर : ऐसी बात नहीं है। वह देने के लिए तैयार हैं लेकिन उसमें कई चीजें होती हैं। हमें उसमें बहुत कुछ देखना होता है। सिर्फ यह नहीं होता कि कोई सरकार पैसा देने के लिए तैयार है तो हम एकदम ले लें। उस पर विचार करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। अगर यह देश के लिए और उन जगहों की प्रगति के लिए आवश्यक होगा तो हम जरूर लेंगे।

श्री गुलाम नबी आजाद : मैं आपका ध्यान बिलाना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार की इसमें कमजोरी नहीं है। क्योंकि जब उनसे ज्यादा पैसा मांगते हैं तो कम्पलीशन सर्टिफिकेट स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए। उसके आधार पर पैसा रिलीज होता है। लेकिन अधिकतर, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जहाँ तक बिहार का सवाल है, वहाँ से सर्टिफिकेट आता ही नहीं है।

श्री शंकर बयाल सिंह : मैंने सांची और मध्य प्रदेश के बौद्ध स्थलों की बात उठायी। बिहार के ऊपर आप इल्जाम लगाकर इस तरह से प्रश्न का उत्तर न दें।

श्री गुलाम नबी आजाद : यू०पी० और बिहार, दोनों स्टेटों की अधिकतर वही हालत है। उनके पहले के प्रोजेक्ट हैं— वे प्रोजेक्ट हैं, बिहार, यू०पी० और

महाराष्ट्र में । जहां तक बिहार और यू.पी. का सवाल है वह बहुत पीछे हैं और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है वह बहुत आगे हैं ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय : वह तो आपका स्टेट है ।

श्री गुलाम नबी आजाद : मेरे स्टेट का सवाल नहीं है (व्यवधान)

श्री राघवजी : यह मध्य प्रदेश का मामला है (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : जब तक हमारी पिछली परफार्मेंस अच्छी नहीं होगी तब तक अगले के लिए पैसा मांगना बड़ा मुश्किल हो जाता है (व्यवधान)

श्री जलालुद्दीन अंसारी : बिहार ने जितनी योजनाएं भेजी हैं, सब लीटा देते हैं, मैं सबूत देना चाहता हूं (व्यवधान)

† شری جلال الدین انصاری : ہمارے
نے جتنی پروجنائیں بھیجی ہیں۔ سب
موٹا دیتے ہیں۔ میں ثبوت دینا چاہتا
ہوں۔۔۔ مداخلت۔۔۔

श्री कैलाश नारायण सारंग : मंत्री महोदय से प्रश्न किया मध्य प्रदेश का और उन्होंने बिहार की बात शुरू कर दी । सवाल यह है कि सांची विश्व विख्यात स्तूपों के लिए और जापान तथा श्रीलंका दोनों राष्ट्र सांची के विकास के लिए इंटरेस्टेड हैं । मध्य प्रदेश सरकार ने 1991-92 में एक बहुत बृहद योजना बनाकर वहां के पहाड़ी विकास के लिए, सुरंग बनाने के लिए एक योजना भेजी थी जिसमें जापान और श्रीलंका भी इंटरेस्टेड हैं । लेकिन विगत 10 वर्षों से सांची के प्रति जिस तरह का दुर्व्यवहार केन्द्र सरकार की ओर से हो रहा है, वह यहां उल्लेखनीय है । मंत्री महोदय, क्या मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस

बृहद योजना के बारे में केन्द्र सरकार ने कुछ विचार किया ? क्या श्रीलंका और जापान सरकार जो वहां करीब दो सौ करोड़ रुपया इनवेस्ट करने के लिए तैयार हैं, क्या उस दृष्टि से भी कुछ आपसे विचार किया या कोई प्रस्ताव है, कोई चर्चा हो रही है ? मंत्री जी यह बताने की कृपा करें ।

श्री गुलाम नबी आजाद : पिछले पांच सालों से चाहे आपकी सरकार हो या हमारी सरकार हो किसी भी मंत्री या मुख्य मंत्री से इस बारे में मुझे कोई चर्चा नहीं की । (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल : कोई प्रस्ताव भेजा है क्या ? (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : चर्चा के बगैर प्रस्ताव कहाँ होगा । चर्चा तक नहीं की (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : मंत्री महोदय, जरा तलाश कर लीजिये । प्रस्ताव लिखित है । मुझे खुद पता है and I am personally interested in it, इसलिए मैं कह रहा हूं ।

श्री गुलाम नबी आजाद : पिछले तीन साल से मैं भी इस मिनिस्ट्री में हूँ । किसी का इंटेस्ट होता तो चर्चा तो करते (व्यवधान)

श्री कैलाश नारायण सारंग : मैं 1991-92 का बोल रहा हूँ (व्यवधान)

श्री लक्ष्मीराम अग्रवाल : आप दिलवा लीजिये... (व्यवधान)

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTI-NAN: Thank you, Mr. Chairman. Though the question pertains to Sanchi, I would like to put a general question with regard to tourism development.

MR. CHAIRMAN: But it has to be focussed on Sanchi.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTI-NAN: Sir, the Minister has replied that the development of tourist facilities at any place is primarily the responsibility of the State Governments. The Department of Tourism, Government of India, extends financial assistance to the State Governments for development of tourist facilities on the basis of proposals received from them. This is the reply. I would like to know whether the proposals of the State Governments have been fully honoured by the Central Government and also whether full financial assistance has been given to the State Governments for completion of those projects. I am asking this because there is a guest house at Rameswaram in Tamil Nadu and for want of financial assistance from the Central Government, there is no compound, cattle; are allowed into the guest house and it is free for all. It is not being utilised at all. I would like to know whether any monitoring facility is provided by the Central Government to find out whether the funds are being utilised properly and also whether full amount has been sanctioned to the State Governments according to the proposals made by them.

SHRIIMATI SUKHBANS KAUR: I would like to reiterate that, tourism being a State Subject, it is primarily the responsibility of the State Government to build the infrastructure. We do give a certain amount of financial assistance and in 99 per cent of the proposals that are given to us in proper form—in the sense that they have to fulfil certain conditions—money is always given to them. There is no question of our not honouring the commitments that we have made.

SHRI PASUMPON THA. KIRUTTI-NAN: I asked a specific question about the guest house at Rameswaram.

SHRI SUKHBANS KAUR: I do Not have the specific answer to that because the question is mainly for Madhya Pra-desh.

श्री बिष्णु का त शास्त्री : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने बार बार यह कहा कि पर्यटन विभाग राज्य विषय है। मैं एक ऐसे प्रकल्प की ओर उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ जो राज्य से अधिक केन्द्र का विषय होना चाहिये। कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे दुर्गम यात्रा है और इस यात्रा के लिए भारत और चीन सरकार के संबंधों पर निर्भर रह कर यात्री जाते हैं। कैलाश मानसरोवर माफी चाहता हूँ, कैलाश मानसरोवर के अंतर्गत है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा के संबंध में मेरे मित्रों ने बताया है कि चीन सरकार के द्वारा दी गयी सुविधाएं ज्यादा अच्छी हैं और भारत सरकार के द्वारा दी गयी सुविधाएं बहुत कष्टकर हैं, नम्बर एक और दूसरा यह है कि यह बहुत खर्चीली यात्रा है। एक एक यात्री को उस पर 30,000 रुपये खर्च करने पड़ने हैं। क्या कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए भारत सरकार तीर्थ यात्रियों को कुछ सहायता भी देना चाहती है जैसे कि हज के यात्रियों को बराबर दी जाती है ?

MR. CHAIRMAN: is the Minister willing to answer?

SHRI GHULAM NABI AZAD: No, Sir.

श्री बिष्णु का त शास्त्री : राज्य और केन्द्र के बारे में तो बताएं।

MR. CHAIRMAN, It does not relate to this question.

Refusal by Qaltar to Air India flight to land

*563. SHRI VIRENDRA KATARIA

SHRI SURESH
KALMADI:

Will the Minister of CIVIL AVIATION AND TOURISM be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Qatar refused an Air India flight to land in its territory on 21st of April, 1995.

The question was actually asked on the floor of the House by Shri Virendra Kataria.